संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा के लिए संघर्ष विराम प्रस्ताव पारित किया

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल एक प्रस्ताव पारित कर रमजान के महीने के लिए गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है। इस पहल ने पांच महीने के गतिरोध को तोड़ा है। इससे पहले अमेरिका युद्ध समाप्त करने के आह्वान को वीटो करता रहा है। इस वजह से इजराइल के सैन्य हमले में मानवीय क्षति बढ़ती गई। यह प्रस्ताव 14 वोट से पारित हुआ। अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में सभी बंधकों की बिना शर्त और तत्काल रिहाई की मांग की गई है।

अभी यह साफ नहीं है कि इजराइल और हमास इस आह्वान को मानते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रस्ताव पारित करने की अनुमति देने के लिए अमेरिका की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन दौरा रद्द कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान राजपरिवार के साथ बिताए बेहद पारिवारिक पल, साझा किए चित्र

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गत दिनों भूटान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक ने उन्हें अपने राजमहल में निजी रात्रि भोज के लिए भी आमंत्रित

किया। लिंगकाना महल में आयोजित रात्रिभोज की मेजबानी खुद भूटान नरेश ने की। इस दौरान उनका पूरा परिवार भी उपस्थित था। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश के बच्चों के साथ खासा समय बिताया, उनसे हंसी-मजाक और बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वे चित्र साझा किए हैं, जिनसे एक पारिवारिक भाव से जुड़ाव का संकेत मिलता है।

मोइज्जू को पूर्व राष्ट्रपति सोलिह की सलाह, जिद छोड़ कर भारत से मतभेद सुधारना चाहिए

माले। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को सलाह दी है कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें अपनी जिद छोड़ कर पड़ोसी देश भारत से बातचीत करनी चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू को चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जाता है जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। सोलिह ने कहा, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, जिससे पता चलता है कि मोइज्जू कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के

लिए भारत से बात करना चाहते हैं। मालदीव के सामने जो आर्थिक चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उसमें कहीं भी भारत के कर्ज का रोल नहीं है। मालदीव पर चीन का 18 बिलियन मालदीवियन रूफिया का कर्ज है, जबकि भारत का महज 8 बिलियन मालदीवियन रूफिया का। भारत के मामले में मालदीव को 25 साल के अंदर भुगतान करना है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी हमारी मदद करेंगे लेकिन इसके लिए हमें जिद छोड़नी होगी और बातचीत करनी होगी। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोइज्जू ने सोलिह को हरा दिया था।

'मैं तो अभी 33 का कुंवारा हूं', बेरोजगारी से बदहाल चीन में नौकरी के विज्ञापन की शर्तों पर क्यों उबल रहे लोग?

बीजिंग। पड़ोसी देश चीन भले ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हाने का दावा करता हो लेकिन वहां बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है। हालात इतने खराब हैं कि सरकार ने बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया है। पिछले साल जुलाई में चीन में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.3 फीसदी हो गई थी। इस बीच, चीन के एक किराना स्टोर ने 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच के युवा कैशियर की तलाश के लिए नौकरी का एक विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन ने चीनी सोशल मीडिया पर पीड़ादायक पोस्ट की भरमार लगा दी है।सुस्त अर्थव्यवस्था में नौकरी ढूंढ रहे चीनी नागरिक सोशल मीडिया वीबो पर तरह-तरह के पोस्ट कर रहे हैं। विज्ञापन के इस पोस्ट को अब तक 14 करोड़ लोग देख चुके हैं और उस पर करीब 41,000 से ज्यादा लोगों ने भावुक कमेंट किए हैं। पूर्वी प्रांत झेजियांग के निंगबो शहर में एक यूजर ने वीबो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, चीन में नौकरी पाना अब आसान नहीं है।

एक नेटिजन ने लिखा है, क्या आपको लगता है कि अब नौकरी ढूंढना आसान रह गया है? एक अन्य वीबो यूजर ने लिखा, मैं तो इस साल 33 साल का ही हुआ हूं लेकिन तीन साल से नौकरी की तलाश कर रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा है कि यह विज्ञापन आबादी के एक विशाल मध्यम आयु वर्ग(31 से 40) की

दुर्दशा उजागर करता है क्योंकि सरकार उच्च युवा बेरोजगारी दर से लड़ने और कॉलेज स्नातकों में उच्च और रिकॉर्ड बेरोजगारी से निबटने पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है और अधेड़ या 30 से ऊपर की उम्र वाले बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं है। एक युवा यूजर ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए लिखा है, ÷मैं तो अभी 29 साल का ही हूं, अभी अविवाहित हूं और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है लेकिन स्नातक के बाद मुझे तीन बार नौकरी से निकाला जा चुका है। कोई जिम्मेदारी नहीं होने के बावजूद अब, तक किसी कंपनी ने मेरे बायोडाटा का जवाब नहीं दिया है।

एक अन्य यूजर ने गुस्से का इजहार करने वाले इमोजी के साथ पोस्ट किया कि पहले 35 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए नौकरी ढूंढनी मुश्किल थी, वह अब 30 साल की उम्र बाधा तक गिर चुकी है। ऐसी स्थिति में चीन में वैसे बेरोजगारों की संख्या में जबर्दस्त इजाफा हुआ है, जो 30 से ऊपर उम्र के हैं और बाल बच्चेदार हैं। चीन में फिलहाल पुरुषों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष है,जबकि महिलाओं की सामान्य सेवानिवृति की आयु सीमा 55 लेकि कारखानों में काम करने वा महिलाओं को 50 वर्ष में ही रिटा होना पड़ता है।

चीनी किराना स्टोर द्वारा 18 30 साल के लोगों के लिए निका गया ताजा विज्ञापन पहला माम नहीं है। इससे पहले सुपरमार्के श्रृंखला पंगडोंगलाई के एक हाल विज्ञापन में भी इसी तरह भेदभाव का मामला सामने आ था। पंगडोंगलाई ने भी जिन प को भरने की कोशिश की थी, उन लिए अधिकतम आयु 30 व निर्धारित की गई थी। सुपरमार्केट इस पर टिप्पणी करने से इनक कर दिया था।

BLA के हमलों से फिर दहला पाकिस्तान, दूसरे सबसे बड़े नेवल एयर बेस पर भयानक फायरिंग

इस्लामाबाद। पड़ोसी देश पाकिस्तान में मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब वहां के दूसरे सबसे बड़े नौसैनिक हवाई अड्डे पर आतंकियों ने दूसरी बार धावा बोला है और गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों से दहला दिया है। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, यह हमला बलूचिस्तान के तुरबत में स्थित PNS सिद्दीकी नेवल एयर स्टेशन पर हुआ है। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) की माजिद ब्रिगेड ने तुरबत में नौसेना एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, बीएलए का दावा है कि उसके लड़ाके एयरबेस में घुसे हुए हैं। दरअसल, मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीनी निवेश का विरोध करता है और चीन और पाकिस्तान पर उस क्षेत्र के संसाधनों के दोहन का आरोप लगाता रहा है। बीएलए ने इस बेस को निशाना इसलिए भी बनाया है

क्योंकि उस सैन्य अड्डे पर चीनी ड्रोन तैनात हैं। तुरबत का ताजा हमला बीएलए मजीद ब्रिगेड द्वारा सप्ताह का दूसरा और इस साल का तीसरा हमला है। इससे पहले 29 जनवरी को इसने ग्वादर को निशाना बनाया था, जहां सैन्य खुफिया मुख्यालय है। उसके बाद 20 मार्च को भी तुरबत स्थित इसी दूसरे सबसे बड़े नौसेना एयरबेस पर हमला बोला था। 20 मार्च को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में कई विस्फोटों और गोलीबारी की सूचना के बाद शुरू हुई लड़ाई में कम से कम दो पाकिस्तानी सैनिक और आठ आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में बताया है कि आठ आतंकवादियों के एक समूह ने पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें 'सफलतापूर्वक विफल' कर दिया। बता दें कि ग्वादर बंदरगाह चीन द्वारा नियंत्रित है और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का एक अहम हिस्सा और महत्वपूर्ण स्थान है। चीन यहां अरबों डॉलर की सड़कें और ऊर्जा परियोजनाएं बना रहा हैं। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का भी हिस्सा है लेकिन बलूचिस्तान के लोग इसे अपने संसाधानों पर चीन के कब्जे के रूप में देखते हैं। बलूचों का आरोप है कि ग्वादर में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट्स से चीन को फायदा होगा। इसमें स्थानीय हितों की अनेदखी की जा रही है।

अमेरिकी रैपर और रिकॉर्ड निर्माता शॉन कॉम्ब्स के घरों पर छापा

न्यूयॉर्क। संघीय जांच एजेंसी ने अमेरिकी रैपर और रिकॉर्ड निर्माता श कॉम्ब्स के लॉस एंजिल्स और मियामी क्षेत्र में उनके घरों पर छापा मारा कॉम्ब्स को पफ डैडी या डिडी के नाम से भी जाना जाता है। वह कई माह यौन उत्पीड़न जैसे कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइ की रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने है। इस पर कॉम्ब्स के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के प्रवक्ता निकोलस बायसे ने भी कुछ भी कहने से परहेज किया। हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी ने एक बयान में कहा कि न्यूयॉर्क के एजेंटों ने एचएसआई लॉस एंजिल्स, एचएसआई मियामी

और हमारे स्थानीय कानून प्रवर्तन भागीदारों की सहायता से यह कार्रवाई क उल्लेखनीय है कि शॉन कॉम्ब्स पर संगीत निर्माता रॉडनी लिल रॉड जोन्स मुकदमा दायर किया है। उसने उन पर यौन उत्पीड़न और यौनकर्मियों के सा यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। कॉम्ब्स खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों वाला यह पांचवां मुकदमा है। न्यूयॉर्क एक अदालत में दायर मुकदमे पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉम्बस के वकील श होली ने कहा कि यह शुद्ध कल्पना है। हमारे पास इस बात के निर्विवाद सब हैं कि उनके दावे पूरी तरह झूठ हैं।

नेपाल के विदेश मंत्री चीन के नौ दिवसीय दौरे पर, सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने ही कसा तंज

काठमांडू। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ रविवार को नौ दिवसीय यात्रा पर चीन के लिए रवाना हुए। उनकी इतनी लंबी विदेश यात्रा पर सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल के नेताओं ने ही तंज कसा है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय की सचिव सेवा लम्साल ने पत्रकारों को बताया कि विदेश मंत्री श्रेष्ठ की चीन में वहां के विदेश मंत्री के अलावा सीपीसी के कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात तय है, जिनमें स्थाई समिति के सात में से एक नेता, चीन के वाइस प्रीमियर, कम से कम तीन प्रदेश के सीपीसी पार्टी सचिव, सीपीसी के विदेश विभाग के मंत्री प्रमुख हैं।

वहीं विदेश मंत्री श्रेष्ठ की इतनी लंबी यात्रा के लिए सीपीएन (यूएमएल) के नेताओं ने तंज कसा है। सीपीएन (यूएमएल) के प्रचार विभाग के प्रमुख विष्णु रिजाल ने एक्स पर विदेश मंत्री के नौ दिन की लंबी यात्रा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री को इतनी फुर्सत कैसे हो जाती है कि वो 9-9 दिन की चीन यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। नेपाल के विदेश मामलों में कई अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे विदेश मंत्री को रूबरू होना चाहिए। रूस-यूक्रेन में फंसे नेपाली

नागरिकों की सुरक्षित वापसी की चिंता करने के बजाय विदेश मंत्री की 9 दिन की चीन यात्रा पिकनिक जैसी लग रही है। नेपाल सरकार को विदेश मामलों में और कूटनीतिक मामलों में संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

सीपीएन (यूएमएल) की ही राष्ट्रीय सभा की पूर्व सदस्य कोमल ओली ने भी विदेश मंत्री की लंबी यात्रा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि हम विदेश मामलों में कितने गंभीर हैं इस बात का प्रमाण विदेश मंत्री के नौ दिनों की लंबी चीन यात्रा से दिखता है। विदेश मंत्री के कार्यक्रमों में दो या तीन अफिसियल मीटिंग देखा गया है। बाकी सिर्फ कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ चाइना के डेलीगेशन से ही मुलाकात है।

भारत ने वैश्विक मंच पर किया महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्र ने की तारीफ

न्यूयॉर्क। महिला सशक्तिकरण को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीयों के स्थाई मिशन द्वारा बताया गया कि न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर 68वें आयोग में भारत द्वारा मजबूत पक्ष रखा गया।

रुचिरा कंबोज ने रखा मजबूत पक्ष

महिला सशक्तिकरण को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीयों के स्थाई मिशन द्वारा बताया गया कि न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर 68वें आयोग में भारत द्वारा अपना पक्ष रखा गया।

भारत ने की सशक्त पहल

न्यूयॉर्क स्थित भारतीयों के स्थायी मिशन द्वारा ट्वीट किया गया कि न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर 68वें आयोग में भारत ने प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। भारत द्वारा पैनल में अपने विचार रखे गए और सशक्त पहल की गई। इस

वैश्विक मंच पर भारत ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व किया। आगे बताया गया है कि इस बार भारत द्वारा लैंगिग समानता और महिला सशक्तिकरण पर प्रस्तुति दी गई। इस तरह भारत ने महिला सशक्तिकरण को लेकर वैश्विक मंच पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

हमले में शामिल सभी लोगों को सजा मिलेगी राष्ट्रपति पुतिन

मॉस्को। रूस के राष्ट्रप व्लादिमीर पुतिन ने राजधानी मॉस्क के क्रास्नोगोर्स्क शहर के क्रोक सिटी हॉल (संगीत स्थल) में ह आतंकी हमले की कड़ी निंदा की साथ ही 24 मार्च को राष्ट्रीय शो दिवस घोषित किया है। उन्होंने क कि हमले में शामिल सभी लोगों क सजा मिलेगी। पुतिन ने देश संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों को हराना चाहते हैं, रू किसी भी देश के साथ काम करने लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ह बर्बर हमले की जांच की जाएगी। हम में शामिल सभी लोगों को सजा जाएगी। मैं 24 मार्च को राष्ट्रीय शो दिवस घोषित करता हूं। उल्लेखनीय कि मॉस्को के क्रास्नोगोर्स्क शहर क्रोकस सिटी हॉल (संगीत स्थल) हुए हमले में 100 से अधिक लोगों मौत हुई, जबकि सैकड़ों लोग घाय हुए। यह हमला शुक्रवार की शाम हुआ इस हमले की जिम्मेदारी कुख्य आतंकी संगठन इस्लामिक स्टे (आईएसआई) ने ली है।

'दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का अवसर', जयशंकर के सिंगापुर दौरे पर मंत्रालय का बयान

हैती। केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का सिंगापुर दौरा समाप्त हो गया। उनके इस दौरे पर मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान के अनुसार विदेश मंत्री जयशंकर का सिंगापुर दौरा और वहां के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कई क्षेत्रों में प्रगति और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने का अवसर प्रदान करेगा।

पीएम, डिप्टी पीएम से की मुलाकात

जयशंकर 23 से 25 मार्च तक सिंगापुर दौरे पर थे। उन्होंने सिंगापुर पहुंचकर सबसे पहले युद्ध स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग,

उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने कैबिनेट के शीर्ष नेताओं के साथ भी रणनीतिक द्विपक्षीय संबंध और हिंद-प्रशांत एवं पश्चिमी एशिया क्षेत्रों की स्थिति पर भी बात की।

विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ÷इस यात्रा ने भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और सहयोग के क्षेत्रों में प्रगति लाने का अवसर प्रदान किया।÷ बता दें कि जयशंकर ने व्यापार और उद्योग मंत्री गैन किम योंग से अलग-अलग बैठकें की। इस दौरान उन्होंने हरित ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा पर चर्चा की। केंद्रीय विदेश मंत्री ने कानून एवं गृह मामलों के मंत्री के. शनमुगन और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री टिओ ची हीन से भी मुलाकात की।

भारतीय समुदाय से भी मिलें

:जयशंकर ने सिंगापुर में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने थिंक टैंक और नीति निर्माताओं से बातचीत की। जयशंकर ने इस दौरान वहां वैश्वीकरण के उदाहरण पर जोर दिया। उन्होंने विदेश नीति पर भी बात की और इसके महत्व को भी बताया। बता दें कि विदेश मंत्री का फिलीपीन और मलयेशिया की यात्रा करने का भी कार्यक्रम है।

अपने लड़ाकू विमान बेचने को तैयार हुआ जापान, शांतिवादी सिद्धांत छोड़कर पहली बार लिया बड़ा फैसला

टोक्यो। जापान द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान ने अपने शांतिवादी सिद्धांतों को छोड़कर लड़ाकू विमान बेचने का फैसला लिया है। जापान अपने लड़ाकू विमानों को ब्रिटेन और इटली के साथ अन्य देशों में विकसित कर रहा है। इस फैसले के बाद जापान संयुक्त लड़ाकू जेट परियोजना में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा।

पहली बार लिया बड़ा फैसला

जापान की कैबिनेट ने हथियार उपकरण के दिशानिर्देशों में संशोधन का भी समर्थन किया। इससे लड़ाकू विमान समेत घातक हथियारों को अन्य देशों को बेचने की अनुमति मिल सकेगी। बता दें कि इससे पहले जापान में शांतिवादी संविधान के तहत हथियारों के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था। अब चीन से बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच उसने यह कदम उठाए हैं।

नए लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जापान

इस समय जापान अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए स्न-2 लड़ाकू विमानों और ब्रिटेन द्वारा उपयोग किए जाने वाले यूरोफाइटर टाइफून को बदलने के लिए नई तकनीकि के लड़ाकू विमानों को तैयार कर रहा है। इस काम में इटली और ब्रिटेन जापान का सहयोग कर रहे हैं। इस कार्य योजना को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम नाम दिया गया है, जिसका मुख्यालय ब्रिटेन में है। इससे पहले जापान एफ-एक्स नाम के एक घरेलू डिज़ाइन पर काम कर रहा था। जापान को उम्मीद है कि उसके द्वारा तैयार किया गया नया विमान रूस और चीन के खिलाफ बढ़ते तनाव के

बीच उन्नत हथियार साबित होगा।

संविधान में किया गया यह संशोधन

जापान की कैबिनेट ने हथियारों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दिशानिर्देशों में भी संशोधन का समर्थन किया है। इससे घातक हथियारों को अन्य देशों को बेचने की अनुमति मिल सकेगी। जापान ने शांतिवादी संविधान के तहत लंबे समय से हथियारों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन चीन से बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव के बीच देश ने तेजी से कदम उठाए हैं। जेट विमानों को बेचने के निर्णय से जापान को पहली बार अपने द्वारा उत्पादित घातक हथियारों को अन्य देशों में निर्यात करने की अनुमति तहत जापान ने सैन्य उपकरणों अ घातक हथियारों के सभी निर्यातों प्रतिबंध लगा दिया था। अब ज जापान ने इस संविधान में संशोध किया तो विरोधियों ने प्रधानमं फुमियो किशिदा सरकार आलोचना की है।

इसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि संशोधि दिशानिर्देश फिलहाल केवल लड़ा विमानों पर लागू होते हैं। संभावि खरीदार भी उन 15 देशों के हो जिनके साथ जापान ने र साझेदारी सौदे पर हस्ताक्षर किए इस बदलाव ने जापान के लि अमेरिका द्वारा डिजाइन की पैट्रियट मिसाइलों को अमेरिका बेचने का रास्ता साफ कर दिया है

मॉस्को में हमले से पहले आतंकियों ने की थी तुर्किये की यात्रा

हैती। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। यहां चार आतंकियों ने एक कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी बरसाई थीं, जिसमें कम से कम 143 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा घायल हैं। अब इस घटना को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट में तुर्किये के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से एक चौंकाने वाला दावा किया है। बताया गया कि मॉस्को में हमला करने से पहले सभी बंदूकधारी तुर्किये गए थे।

तुर्किये के सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बंदूकधारी अपने रूसी निवास परमिट को रिन्यू कराने उसी सप्ताह कुछ समय के लिए तुर्किये गए थे। हालांकि, इन आतंकियों ने वहां कोई हंगामा नहीं किया था।

कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था

तुर्किये के सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि हमलावरों के खिलाफ उस समय कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था, इसलिए उन्हें तुर्किये और रूस के बीच यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा, यह भी पता चला कि हमलावर कई समय से मॉस्को में रह रहे थे। दो हमलावर दो मार्च 2024 को तुर्किये से रवाना होकर मॉस्को गए। बाद में पता चला कि मॉस्को में इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने हमला किया, जिसमें 143 से अधिक की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए हैं।

चार बंदूकधारी गिरफ्तार

इस घटना के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट जारी करते हुए रूस की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया। अब तक इस घटना पर 11 संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से चार वह बंदूकधारी हैं, जो हमले में सीधे तौर पर शामिल रहे। अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों को पुलिस ने कार से पीछा करने के बाद दबोचा।

पुतिन यूक्रेन को ठहरा रहा जिम्मेदार

वहीं एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में हुए हमले में इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार ठहराने से मना कर दिया है। इसके बजाय उन्होंने दावा किया है कि हमलावरों का यूक्रेन से संबंध हैं। उनका कहना है कि हमलावरों ने यूक्रेन भागने की कोशिश क्यों की। जबकि हमलावरों के यूक्रेन भागने के दावे को कीव पहले ही खारिज कर चुका है। हालांकि, सोमवार को दिए बयान में पुतिन ने माना कि कट्टरपंथी इस्लामवादी ने इस हमले को अंजाम दिया है, लेकिन उनके यूक्रेन से संबंध थे।

पुतिन ने पूछते हुए कहा, %सवालों के जवाब मिलना वाकई जरूरी है। आखिर हमलावरों ने यूक्रेन भागने की कोशिश क्यों की? वहां उनका कौन इंतजार कर रहा था?% उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अपने सैटेलाइटों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस घटना में कीव का कोई हाथ नहीं है और आईएस ने हमले को अंजाम दिया है।